सिविल अपील

डी.के. महाजन, न्यायमूर्ति के समक्ष

शेरा,—*अपीलकर्ता।*

बनाम

जिवानी, — *प्रतिवादी।*

नियमित द्वितीय अपील 1961 *की सं.* 1754

14 *जुलाई*, 1972.

*हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (*1956 *का LXXVIII) - धारा* 4, 5, 9, 10 और *11* (vi) - एक बच्चे और *एक वयस्क को गोद लेना* - कहा गया - एक वयस्क के मामले में देने और लेने के समारोह का गैर-प्रदर्शन - क्या गोद लेने को अमान्य करता है।

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 4, 5, 9, 10 और 11 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि बच्चे को गोद लेने और वयस्क को गोद लेने के बीच अंतर है। अधिनियम किसी वयस्क को गोद लेने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि उस गोद लेने को प्रथा द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता है और यह धारा 11 के खंड (vi) से स्पष्ट है। गोद लेने का अधिकार माता-पिता या अभिभावक में निहित किया गया है और इस अवधारणा का तात्पर्य है कि यह केवल उन व्यक्तियों से संबंधित है, जो *सुई जूरी नहीं हैं*, यानी, जो नाबालिग हैं। एक वयस्क या एक वयस्क को अभिभावक या माता-पिता द्वारा नहीं सौंपा जा सकता है। उसे केवल उसकी सहमति से गोद लिया जा सकता है। इसलिए, जहां तक एक वयस्क का संबंध है, देने और लेने का समारोह अपना सारा महत्व खो देता है क्योंकि वह अकेले गोद लिए जाने के लिए अपनी सहमति दे सकता है। उसे गोद नहीं दिया जा सकता। धारा 11 (vi) पूरी तरह से अनुचित है और साथ ही उस पर लागू नहीं होती है। इसलिए एक वयस्क के मामले में देने और लेने के समारोह का गैर-प्रदर्शन गोद लेने को अमान्य नहीं करता है।

हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री चेतन दास की अदालत के दिनांक 31 जुलाई, *1961 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील*, जिसमें भिवानी के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री बीआर गुलियानी द्वारा दिनांक 12 अगस्त, *1960 को की गई* डिक्री की पुष्टि करते हुए मुकदमे को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था।

तिरलोक नाथ भल्ला, *अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।*

एच. एल. सरीन, सीनियर *अधिवक्ता* और एम. एल. सरीन, *अधिवक्ता*, उत्तरदाताओं *के लिए।*

निर्णय

महाजन, न्यायमूर्ति—यह दूसरी अपील वादी के मुकदमे को खारिज करने वाले न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों के खिलाफ निर्देशित है।

(2) वादी एक शेरा है। गोद लेने के एक लिखित पंजीकृत विलेख द्वारा, उन्हें श्री पटोरी द्वारा गोद लिया गया था। गोद लेने के विलेख में, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया था कि उसकी बेटी या बेटी के बच्चों को उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और यह दत्तक पुत्र को दे दिया जाएगा। हालांकि, श्री पटोरी ने अपनी बेटी और बेटी के बेटे के पक्ष में 30 जून, 1959 और 31 जुलाई, 1959 को दो पंजीकृत विलेखों द्वारा पूरी संपत्ति का उपहार दिया। इसके चलते दत्तक पुत्र ने मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने इस आधार पर अलगाव को चुनौती दी कि वह दत्तक पुत्र होने के नाते, संपत्ति उनके पास निहित है और श्री पटोरी इसे

अलग नहीं कर सकती हैं।

(3) पक्षकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

(1) शुल्क और अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे को उचित रूप से महत्व दिया गया है?

(2) क्या मुकदमा उचित रूप से तैयार किया गया है और वर्तमान रूप में सुनवाई योग्य है?

(3) क्या वादी को वैध रूप से अपनाया गया था; यदि हां, तो किस प्रभाव तक?

(4) क्या वादी विक्रेता के जीवनकाल में अलगाव को चुनौती देने का हकदार है?

(5) क्या पार्टियां रिवाज द्वारा शासित हैं; यदि हां, तो क्या प्रतिवादी नंबर 1 कस्टम के तहत मुकदमे में संपत्ति का निपटान करने के लिए सक्षम नहीं था?

(6) क्या संपत्ति पैतृक है; यदि हां, तो क्या यह प्रथा या कानून के तहत अपरिहार्य है?

(7) क्या वादी को गोद लेने का आरोप लगाने से रोका जाता है?

(4) जहां तक मुद्दे 4 और 7 का संबंध है, मुद्दा संख्या 1 अब विवाद में नहीं है, उन पर निचली अपीलीय अदालत द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, हालांकि वे अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी द्वारा तय किए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि गोद लेना अमान्य था क्योंकि देने और लेने का समारोह नहीं हुआ था और गोद लेने वाला 15 वर्ष से अधिक आयु का था और एक विवाहित व्यक्ति था। वादी के मुकदमे को तदनुसार खारिज कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ, वादी द्वारा निचली अपीलीय अदालत में अपील को प्राथमिकता दी गई और निचली अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक विवाहित व्यक्ति को गोद लेने पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन चूंकि देने और लेने का समारोह नहीं हुआ था, इसलिए गोद लेने को कानून में बुरा माना गया था। हालांकि, निचली अपीलीय अदालत ने शेष मुद्दों पर फैसला नहीं किया, और वास्तव में वे इस निष्कर्ष के बाद नहीं उठे कि कोई वैध गोद नहीं लिया गया था।

(5) वादी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री भल्ला ने तर्क दिया कि गोद लेने की वैधता के सवाल पर निचली अपीलीय अदालत के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट का निर्णय कानून में खराब है। इससे पहले कि मैं इस विवाद से निपटूं, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 78) के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना उचित होगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम पार्टियों पर लागू होता है।

(6) धारा 4 अधिनियम के अभिभावी प्रभाव को दर्शाती है और निम्नलिखित शब्दों में है:-

"4. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान के अनुसार सहेजें, —

(a) इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले लागू हिंदू कानून का कोई पाठ, नियम या व्याख्या या उस कानून के हिस्से के रूप में कोई भी रिवाज या उपयोग किसी भी मामले के संबंध में प्रभावी नहीं होगा, जिसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है;

(b) इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले लागू कोई भी अन्य कानून हिंदुओं पर लागू नहीं होगा, जहां तक कि यह इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है।

धारा 5(1) में प्रावधान है कि दत्तक ग्रहण ोें को अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार विनियमित

किया जाना है और यह निम्नलिखित शर्तों में है:-

"5 (1) इस अध्याय में निहित प्रावधानों के अलावा इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी हिंदू द्वारा या हिंदू को कोई गोद नहीं दिया जाएगा, और उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दत्तक ग्रहण शून्य होगा। -

धारा 9 उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो बच्चे को गोद देने में सक्षम हैं और निम्नलिखित शब्दों में हैं: –

(1) (1) पिता या माता या किसी बालक के अभिभावक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के पास बालक को गोद देने की क्षमता नहीं होगी।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पिता, यदि जीवित है, को अकेले दत्तक ग्रहण में देने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसे अधिकार का प्रयोग माता की सहमति से तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि माता ने पूरी तरह से और अंत में दुनिया को त्याग नहीं दिया है या हिंदू होना बंद कर दिया है या सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मन का घोषित किया गया है।

(3) मां बच्चे को गोद दे सकती है यदि पिता मर चुका है या पूरी तरह से और अंत में दुनिया को त्याग चुका है या हिंदू नहीं है या सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा अस्वस्थ मन का घोषित किया गया है।

(4) जहां पिता और माता दोनों मर चुके हैं या पूरी तरह से और अंत में दुनिया को त्याग चुके हैं या सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा अस्वस्थ मन के घोषित किए गए हैं, तो बच्चे का अभिभावक (चाहे वह अदालत द्वारा घोषित वसीयतनामा अभिभावक या अभिभावक हो) अदालत की पूर्व अनुमति के साथ बच्चे को गोद दे सकता है।

(5) उपधारा (4) के तहत अभिभावक को अनुमति देने से पहले, अदालत इस बात से संतुष्ट होगी कि गोद लेना बच्चे के कल्याण के लिए होगा, इस उद्देश्य के लिए बच्चे की उम्र और समझ को ध्यान में रखते हुए बच्चे की इच्छाओं पर उचित विचार किया जाएगा और यह कि अनुमति के लिए आवेदक को प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं दी गई है और किसी भी व्यक्ति ने इसे बनाने या देने के लिए सहमति नहीं दी है या देने के लिए सहमति नहीं दी है। आवेदक को गोद लेने के विचार में कोई भुगतान या इनाम दिया जाता है, सिवाय इसके कि अदालत मंजूरी दे सकती है।

(7) धारा 10 में उन व्यक्तियों की गणना की गई है जिन्हें गोद लिया जा सकता है जो निम्नलिखित शब्दों में हैं: –

कोई भी व्यक्ति तब तक गोद लेने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, अर्थात्:-

(1) वह या वह एक हिंदू है;

(ii) उसे पहले से गोद नहीं लिया गया है;

(iii) उसकी शादी नहीं हुई है, जब तक कि पार्टियों पर लागू कोई रिवाज या उपयोग नहीं है जो विवाहित व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देता है;

(iv) उसने पंद्रह साल की उम्र पूरी नहीं की है, जब तक कि पार्टियों पर लागू कोई

रिवाज या उपयोग लागू न हो जो पंद्रह साल की उम्र पूरी करने वाले व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देता है।

धारा 11 वैध दत्तक ग्रहण के लिए शर्तों को निर्धारित करती है और निचली अपीलीय अदालत द्वारा जिस प्रमुख शर्त पर भरोसा किया गया है, वह शर्त संख्या 12 है। (iv) जो निम्नलिखित शब्दों में है -

"गोद लिए जाने वाले बच्चे को वास्तव में संबंधित माता-पिता या अभिभावक द्वारा या उनके अधिकार के तहत गोद दिया जाना चाहिए और बच्चे को उसके जन्म के परिवार से गोद लेने वाले परिवार में स्थानांतरित करने के इरादे से लिया जाना चाहिए:

बशर्ते कि *दत्तहोमम* का प्रदर्शन गोद लेने की वैधता के लिए आवश्यक नहीं होगा।

(8) प्रावधानों के संयुक्त पठन से एक बात स्पष्ट है कि एक बच्चे को गोद लेने और एक वयस्क को गोद लेने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। अधिनियम किसी वयस्क को गोद लेने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि उस गोद लेने को प्रथा द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता है। धारा 11 का खण्ड (vi) स्वयं इस बात का संकेत देता है कि मैंने क्या कहा है। देने का अधिकार माता-पिता या अभिभावक में निहित किया गया है और इस अवधारणा का तात्पर्य है कि यह केवल उन व्यक्तियों से संबंधित *है जो सुई जूरी नहीं हैं* यानी, जो नाबालिग हैं। एक वयस्क या एक वयस्क को अभिभावक या माता-पिता द्वारा नहीं सौंपा जा सकता है। उसे केवल उसकी सहमति से गोद लिया जा सकता है। इसलिए, गोद लेने के मामले में एक बच्चे और एक वयस्क के बीच अंतर को ध्यान में रखना गलत नहीं होगा, जिसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस भेद को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया था। जहां तक एक वयस्क का संबंध है, देने और लेने का समारोह अपने सभी महत्व खो देता है क्योंकि वह अकेले गोद लिए जाने के लिए अपनी सहमति दे सकता है। उसे गोद नहीं दिया जा सकता। उसकी सहमति के बिना उसे गोद नहीं लिया जा सकता। इसलिए, उनके मामले में धारा 11 (vi) पूरी तरह से अनुचित होने के साथ-साथ लागू भी होगी।

(9) निचली अदालत ने धारा 10 (4) पर भी ध्यान नहीं दिया जब उसने कहा कि एक विवाहित व्यक्ति या 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता है। इस मामले पर, रिवाज के नियम को बचाया गया है। जहां तक पंजाब राज्य का संबंध है, हमें केवल रैटिगन के डाइजेस्ट ऑफ परम्परागत कानून का उल्लेख करना होगा जिसमें कई प्राधिकारी ऐसे पाए जाएंगे जहां जाटों के बीच विवाहित व्यक्ति को गोद लेने को वैध ठहराया गया है। निचली अपीलीय अदालत को भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसने केवल इस आधार पर गोद लेने को बुरा माना कि देने और लेने का समारोह साबित नहीं हुआ था। वर्तमान मामले के तथ्यों पर उस समारोह का कोई अर्थ नहीं था और इसके होने का सवाल ही नहीं उठता।

(10) इसलिए, मेरा स्पष्ट रूप से विचार है कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने यह मानने में गलती की थी कि दत्तक ग्रहण खराब था। मेरी राय में, यह एक पूरी तरह से वैध गोद लेने वाला था और मैं तदनुसार मानता हूं।

(11) मैं पहले ही देख चुका हूं कि निचली अपीलीय अदालत ने शेष मुद्दों पर निर्णय नहीं किया। इसलिए, इस मामले को निर्णय के लिए निचली अपीलीय अदालत में भेजना उचित होगा।

पक्षकारों को 7 अगस्त, 1972 को निचली अपीलीय अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी